भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2580

02 अगस्त, 2022 को उत्तर के लिए नियत

इलेक्ट्रिक वाहन नीति

2580. श्री चंद्र शेखर साहू:
डॉ. प्रीतम गोपीनाथ राव मुंडे:
श्री गिरीश भालचन्द्र बापट:
श्री राहुल रमेश शेवाले:

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार के पास देश भर में इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए कोई रणनीति प्रस्तावित है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) आज की तिथि तक इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी देने वाले राज्यों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या यह सच है कि देश में ईवी के उपयोग के लिए प्रोत्साहन प्रत्येक राज्य में भिन्न-भिन्न हैं और यदि हां, तो उसका ब्यौरा और कारण क्या हैं;

(घ) क्या केंद्र सरकार का विभिन्न राज्यों विशेषकर ओडिशा, मुंबई, महाराष्ट्र और पुणे में ईवी के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने के लिए कोई कदम उठाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;और

(ड.) ओडिशा, मुंबई, महाराष्ट्र और पुणे में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए आज की तिथि तक स्थापित/स्थापित किए जाने वाले चार्जिंग स्टेशनों का स्थान-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री

(श्री कृष्ण पाल गुर्जर)

(क): महोदय, देशभर में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने भारत में (हाइब्रिड और) इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण (फेम इंडिया) स्कीम संपूर्ण भारत में 2015 में शुरू की और वर्तमान में, फ़ेम इंडिया स्कीम के चरण-II को 01 अप्रैल, 2019 से 5 वर्ष की अवधि के लिए कुल 10,000 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता से कार्यान्वित किया जा रहा है। इस चरण में सार्वजनिक और साझा परिवहन के विद्युतीकरण पर ध्यान केंद्रित किया गया है और सब्सिडी के माध्यम से 7090 ई-बसों, 5 लाख ई-तिपहिया, 55000 ई-चौपहिया यात्री कारों और 10 लाख ई-दुपहिया वाहनों के लिए

सहायता प्रदान करने का लक्ष्य है। इसके अतिरिक्त, इलेक्ट्रिक वाहन के प्रयोक्ताओं के बीच रेंज की चिंता का निराकरण करने के लिए चार्जिंग अवसंरचना के सृजन के लिए भी सहायता दी गई है।

साथ ही, देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिए सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

i. फ़ेम इंडिया स्कीम चरण-II के अंतर्गत इलेक्ट्रिक दुपहिया वाहनों के लिए 11 जून, 2021 से वाहन लागत की 20% सीमा को बढ़ाकर 40% करके मांग प्रोत्साहन को 10,000 रुपये/किलोवाट घंटे से बढ़ाकर 15,000 रुपये/किलोवाट घंटा कर दिया गया है, जिससे इलेक्ट्रिक दुपहिया वाहनों की लागत अंतर्दहन इंजन वाले दुपहिया वाहनों के बराबर हो गई है।

ii. सरकार ने देश में बैटरी की कीमतों को कम करने के लिए देश में उन्नत रसायन सेल (एसीसी) के विनिर्माण हेतु उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम को 12 मई, 2021 को मंजूरी दी। बैटरी की कीमत में गिरावट से इलेक्ट्रिक वाहनों की लागत में कमी आएगी।

iii. ऑटोमोबिल और ऑटो घटकों के लिए उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम में इलेक्ट्रिक वाहन शामिल हैं जिसे कुल 25,938 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय से दिनांक 15 सितंबर, 2021 को पाँच वर्ष की अवधि के लिए अनुमोदित किया गया है।

iv. इलेक्ट्रिक वाहनों पर वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) 12% से घटाकर 5% और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जर/चार्जिंग स्टेशनों पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है।

v. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने घोषणा की है कि बैटरी से चलने वाले वाहनों को हरे रंग की लाइसेंस प्लेट दी जाएगी और उन्हें परमिट लेने की आवश्यकता नहीं होगी।

vi. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर राज्यों को इलेक्ट्रिक वाहनों पर पथकर माफ करने की सलाह दी है जिससे इलेक्ट्रिक वाहन की शुरुआती लागत को कम करने में मदद मिलेगी।

(ख): जी हाँ। इलेक्ट्रिक वाहनों के संवर्धन के लिए अठारह राज्यों (आंध्रप्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना, हरियाणा, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, गुजरात, असम, गोवा, मेघालय, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड) ने विशिष्ट ईवी नीतियाँ अनुमोदित/अधिसूचित/तैयार की हैं।

(ग): जी नहीं। फ़ेम इंडिया स्कीम के चरण-II के अंतर्गत,यह प्रोत्साहन बैटरी क्षमता से संबद्ध है अर्थात् वाहन लागत की 20% की सीमा के साथ ई-तिपहिया और ई-चौपहिया वाहनों के लिए 10,000 रुपये/किलोवाट घंटा है। इसके अतिरिक्त, ई-दुपहिया वाहनों के लिए 11 जून, 2021 से वाहन लागत की 20% की सीमा को बढ़ाकर 40% करते हुए

प्रोत्साहन/सब्सिडी को 10,000 रुपये/किलोवाट घंटे से बढ़ाकर 15,000 रुपये/किलोवाट घंटा कर दिया गया है।

(घ) और (ङ): महोदय, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग अवसंरचना की स्थापना को सुविधाजनक बनाने के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

i. **फेम-इंडिया स्कीम:** भारी उद्योग मंत्रालय ने फेम इंडिया स्कीम के चरण-II की शुरुआत की है जिसमें इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग अवसंरचना की स्थापना हेतु 1000 करोड़ रुपये का प्रावधान है।

ii. **ग्रिड कनेक्टिविटी और सुरक्षा विनियमः** केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने ग्रिड कनेक्टिविटी से संबंधित तकनीकी मानकों और चार्जिंग स्टेशनों के लिए आपूर्ति संबंधी सुरक्षा विनियमों में संशोधन जारी किए हैं।

iii. **दिशा-निर्देश और मानक:** विद्युत मंत्रालय ने 14.01.2022 के पत्रांक 12/2/2018-ईवी (कंप्यूटर संख्या 244347) के माध्यम से इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग अवसंरचना हेतु संशोधित समेकित दिशानिर्देश और मानक जारी किए हैं।

iv. **केंद्रीय नोडल एजेंसी:** दिनांक 01.10.2019 को जारी दिशानिर्देशों के प्रावधानों के तहत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) को केंद्रीय नोडल एजेंसी (सीएनए) के रूप में चुना गया है।

v. **गो इलेक्ट्रिक अभियान:** विद्युत मंत्रालय ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारी उद्योग मंत्रालय और नीति आयोग के साथ मिलकर ई-मोबिलिटी के लाभों पर आम जनता को शिक्षित करने, संभावित ईवी मालिकों को ईवी अपनाने के लिए सरकारी प्रोत्साहनों के बारे में अवगत कराने, इलेक्ट्रिक वाहनों के बारे में जिज्ञासा उत्पन्न करने और इस जिज्ञासा को मांग में बदलने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान- "गो इलेक्ट्रिक" 19.02.2021 को शुरू किया है।

भारी उद्योग मंत्रालय ने फेम इंडिया स्कीम के चरण-I के अंतर्गत 520 चार्जिंग स्टेशन/अवसंरचना स्वीकृत की। साथ ही, इस मंत्रालय ने फेम इंडिया स्कीम के चरण-II के अंतर्गत 25 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 68 शहरों में 2,877 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन और 9 एक्सप्रेसवे और 16 राजमार्गों पर 1576 चार्जिंग स्टेशनों को भी मंजूरी दी है। 15 जुलाई, 2022 की स्थिति के अनुसार, फेम इंडिया स्कीम,चरण-I और II के अंतर्गत कुल 532 चार्जिंग स्टेशन (फ़ेम-I के अंतर्गत 479 और फ़ेम-II के अंतर्गत 53) स्थापित किए गए हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से प्राप्त के मुताबिक, 01-07-2022 की स्थिति के अनुसार, देश में तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) के खुदरा बिक्री केन्द्रों पर कुल 3448 चार्जिंग स्टेशन संस्थापित किए गए हैं। विवरण **अनुलग्नक-क** पर है।

***

अनुलग्नक-क

तेल विपणन कंपनियों द्वारा अपने खुदरा बिक्री केंद्र)आरओ(पर 1.7 2022.के अनुसार प्रचालित इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	**खुदरा बिक्री केंद्रों की संख्या जहां इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग सुविधा उपलब्ध है**
अंडमान और निकोबार	2
आंध्र प्रदेश	191
अरुणाचल प्रदेश	9
असम	61
बिहार	87
चंडीगढ़	14
छत्तीसगढ़	115
दिल्ली	75
गोवा	31
गुजरात	219
हरियाणा	199
हिमाचल प्रदेश	33
झारखंड	47
संघ राज्यक्षेत्र जम्मू और कश्मीर	26
कर्नाटक	250
केरल	102
लक्षद्वीप	1
मध्य प्रदेश	242
महाराष्ट्र	**183**
मणिपुर	16
मेघालय	8
नगालैंड	6
ओडिशा	**118**
पुदुचेरी	3
पंजाब	125
राजस्थान	281
तमिलनाडु	235
तेलंगाना	224
त्रिपुरा	16
दादरा और नगर हवेली तथा दमण और दीव	1
उत्तर प्रदेश	308
उत्तराखंड	43
पश्चिम बंगाल	177
कुल योग	**3448**

फेम-I के अंतर्गत कार्यशील चार्जिंग स्टेशन:

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम	फेम-I के अंतर्गत कार्यशील चार्जिंग स्टेशन
1.	तेलंगाना	57
2.	झारखंड	30
3.	गोवा	30
4.	कर्नाटक	65
5.	हिमाचलप्रदेश	9
6.	उत्तरप्रदेश	16
7.	राजस्थान	49
8.	दिल्ली	94
9.	चंडीगढ़संघराज्यक्षेत्र	48
10.	दिल्ली-जयपुर-आगराराजमार्ग	31
11.	मुंबई-पुणेएक्सप्रेसवे	17
12.	जयपुर-दिल्लीराजमार्ग	9
13.	दिल्ली-चंडीगढ़राजमार्ग	24
कुल		**479**

फेम-II केअंतर्गत कार्यशील चार्जिंग स्टेशन:

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम	नगर	फेम-II के अंतर्गत कार्यशील चार्जिंग स्टेशन
1.	दिल्ली	दिल्ली	15
2.	महाराष्ट्र	नवी मुंबई	1
3.		नागपुर	7
4.	तमिलनाडु	चेन्नई	8
5.	केरल	त्रिशूर	8
6.		एरनाकुलम	6
7.		कन्नूर	2
8.	गुजरात	अहमदाबाद	2
9.	कर्नाटक	बेगलुरु	1
10.	मध्यप्रदेश	इंदौर	2
11.	राजस्थान	जयपुर	1
	कुल		**53**

*****